B.A.(Education),Part-1,Paper-ll
Presented by Dr.Pallavi
Topic- Indian Education Commission (Hunter Commission)1882)

7.4 भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन) 1882 [Indian Education Commission

(Hunter Commission) 1882] :

लार्ड रिपन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे, इंग्लैंड में जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इंडिया के सदस्यों भारत आने से पूर्व वचन देकर आये थे कि भारत में जनसामान्य को शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे लाड रिपन ने भारत आकर अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया। उन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग (Indian Education Commission) की नियुक्ति 1882 में को और गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हण्टर को इसका अध्यक्ष बनाया। इस कमीशन में 20 सदस्य थे जिनमें 9 भारतीय थे। कमीशन की 700 पृष्ठों को रिपोर्ट में शिक्षा के प्रत्येक स्तर के उन्नयन के लिए सिफारिश की गयी।

कमीशन के रिपोर्ट पर कार्यवाही हुई और इसका स्पष्ट प्रभाव भारत में अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति के रूप में प्रतिबिम्बित होने लगा।

7.4.1 आयोग की सिफारिशों का प्रभाव (Impact of Commission Recommendation) हण्टर कमीशन द्वारा भारत में शिक्षा के व्यापक क्षेत्र में दी गयी संस्तुतियों तथा उनके प्रभावों के परिणाम
तुरन्त प्रकट होने लगे। आयोग की संस्तुतियों के लागू होते हो इन क्षेत्रों में प्रभाव विकसित होने लगा।

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा

आयोग को सिफारिशों के अनुसार देश में महाविद्यालयों को संख्या में वृद्धि होने लगी। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर में हुई 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय का विस्तार लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज से हुआ। इसमें विश्वविद्यालय की फैकल्टो थी। बाद में इसमें लॉ फैकल्टी (Law Faculty) भी आरम्भ हुई। ओरियन्टल फैकल्टी में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी फारसी तथा संस्कृत में उपाधि (degree), डिप्लोमा भीविश्वविद्यालय का विस्तार लातूर युनिवर्सिटी कॉलेज से हुआ। इसमें विश्वविद्यालय की फैकल्टी थी । बाद में इसमें ल फैकल्टी (L.aw Faculty) भी आरम्भ हुई। ओरियन्टल फैकल्टी में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का न होकर मातृभाषा थी। यह विभाग अरबी, फारसी तथा संस्कृत में उपाधि (degree), डिप्लोमा भी
प्रदान करता था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है, 1869 ई० में उत्तरी भारत में एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव लाया गया था।

| .जुलाई 1872 के लाड प्यार (तत्कालीन गवर्नर नार्थ वेस्ट प्राविस) ने भवन केन्द्रित (Nucleus) कॉलेज खोला, जो म्योर सेन्ट्रल कॉलेज के नाम से आज भो, जाना जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय को स्थापना के बाद से यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि संयुक्त प्रांत (Unitcd Province) में भी एक विश्वविद्यालय खोला जाय। उस समय तक सभी प्रांतों के कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय सें सम्बद्ध में। अनेक कारणों में महाविद्यालयों के संबद्धीकरण एवं संचालन में परेशानिया आ रहा थी। इसलिए |887 ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में

आया। 19वीं सदी के अन्त तक भारत में पांच विश्वविद्यालय हो गये थे। द्वार को छोड़कर शेष सभी चार विश्वविद्यालयों ने साईस फैकल्टी आरम्भ की और एम मो को वीडियो देना आरंभ किया।

आयोग  की सिफारिशों ने महाविद्यालयी शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। माध्यमिक शिक्षा पर बढ़ते दबाव के कारण उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोले जाने लगे । छात्र भी यह अनुभव करने लगे कि सरकार में अच्छे पदों पर काम करने के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है।

आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को भी बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मिशनरियों ने 37 कॉलेज खोले और 42 कॉलेज निजी प्रचन्ध में खुले । 1882 में कॉलेजों की संख्या 68 थों जो 1902 तक 179 हो गयी । इनमें 9 कॉलेज सीलोन (लंका) में खुले और 2 बर्मा में इनमें 138 कॉलेज ब्रिटिश भारत में थे । इनमें 12 कॉलेज लड़कियों के थे तथा ।। कॉलेज यूरोप के लोगों के लिए ये। मिशनरियों के विरोध के कारण सरकार ने उच्च शिक्षा में कोई विशेष रूच नहीं दिखायो। अन्तः लयाँ पर भारतीयों का ही नियंत्रण रहा।

1885 ई. में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तथ स्वाधीनता आंदोलन से देश में शैक्षिक प्रगति हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने इस सम्बन्ध में कहा है- 'लगभग दो पीढ़ियों से हजारों छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा दी गयी । अंग्रेजी की व्यावहारिक उपयोगिता के साथ-साथ उन्हें अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन भी करना पड़ा और साथ ही स्वतंत्रता का साहित्य भी बंगाल के मस्तिष्क में बेकन, मिल्टन, लॉक, बर्क, वॉइस बर्क, बायरन आदि के विचार पूछ रहे थें । आत्मानुभूति तथा आत्माभियान की भावना में विकसित हो रही थी। पूर्व के विचारों से इन विचारों का मेल संभव नहीं था। इसका राजनीतिक परिणाम भी सामने आ रहा था। बौद्धिक आंदोलन प्रगति पर था और 1882 के बाद नयी विचारधारा का शक्तिशाली प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा था।'

इस काल में स्वाधीनता आंदोलन की भूमिका शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण रही है। छोटे-छोटे हाई स्कूल, कॉलेजों में परिवर्तित हो गये। भारतीयों के अपने राष्ट्रीय चरित्र के विकास का अहसास होने लगा था। यें हाई स्कूल तथा कॉलेज अंग्रेजों हेडमास्टरों तथा प्रिंसीपलों की निगरानी में चल रहे थे ।योग्य भारतीय हेडमास्टर तथा प्रिंसीपलों का अभाव था। प्रसिद्ध शिक्षक आर० पो० परांजवे ने इस दिशा में कार्य किया। कुछ अध्यात्मवादी, सुधारवादी व्यक्तियों ने सरकारी नौकरियों में जाने की बजाय शिक्षा संस्थाओं को बागडोर संभाली। पूना का फर्ग्युसन कॉलेज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी० जी० चिफ लोग कर तथा जी० जी० अगरकर द्वारा स्थापित हुआ। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता के रिपन कॉलेज का भार संभाला ।

आर्य समाज आंदोलन ने देश भर में डी० ए० एवं आर्य शिक्षण संस्थाओं का जाल फैलाया ।
1898 ई० में श्रीमती एनी बेसेन्ट (Mrs. Annie Besant) ने सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज स्थापना बनारस में की जो कालान्तर में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ।

2. माध्यमिक शिक्षा

हण्ट कमीशन की सिफारिशों के बाद माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक विकास कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के 10 वर्ष के भीतर माध्यमिक शिक्षा को प्रगति में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 1902 में गयी इनमें 2,14,007 लाख एवं 5.90.129 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे थे । माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के प्रति अति उत्साह था। इसका कारण प्राथमिक शिक्षा को प्रगति था। निजी स्कूलों में कुछ के सरकारी सहायता  (Grant In-aid) मिल रही थी। अन्य विद्यालय आमदनी के अनुसार चल रह थे ।  शिक्षा  विभाग भी इन प में बाधा नहीं डाल रहा था।

आयोग ने कोर्म B कं अन्तर्गत औद्योगिक (Industrial) मा व्यावसायिक (commercial) पाठ्यक्रम रखे । 19 वी सदी के अन्त तक कोर्स B में विशेष प्रगति नहीं हुई। राज्य सरका ने कुछ पाठ्कमों मे प्रयोगात्मक शिक्षा की वह भी की। 1886 में मद्रास में टेकनोकल पाव्यकम शुरू कियी । 1897 में मुम्बई सरकार ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate SLC) परीक्षा आरम्भ की जिसके आधार पर छात्र , युनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए योग्यता अर्जित करते थे । स्कूल फाइनल (School Final) परीक्षा प्रारम्भ की। पंजाब में क्लर्क एवं वाणिज्य को शिक्षा आरम्भ की । चंगाल ें भी क्लक एवं चिराग के पार आर्य किये। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों से संबंधित पोजनाओं को कायन्वित किया कि मैट्रिकुलेशन परीक्षा पर अधिक ल दिया जाता रहा। 1902 में मैट्रिक में 23000 ml ने परीक्षा दो जैकी B कोर्स में कुल 2000 छात्र ही बैठे ।

इतना सब होने पर भी शिक्षा के माध्यम की स्पष्ट नीति के कारण किसी भी प्रदेश में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम न बन सका ।

3. प्राथमिक शिक्षा

आयोग ने स्थानीय निकायों, जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं को इंग्लैंड की कंट्री कौंसिल (County Councils) के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपा। इस व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति तो हुई पर आशा के अनुरूप नहीं। स्थानीय निकायों के अधिकार निर्धारित किये गये परम्मरागत देशों विद्यालय भी स्थानीय निकायों की परिधि में जिन स्थानों पर स्थानीय निकायों को शैक्षिक अधिकार नहीं दिये गये, वहाँ पर सरकार पाठशालायें खोली गयीं।

प्राथमिक शिक्षा के खर्च के वहन करने के लिए नियम बनाये गये। निकायों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित पैसा प्राथमिक शिक्षा के लिए हो व्यय किया जाये । बम्बई सरकार ने आधी धनराशि स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए दी। बंगाल, पंजाब, संयुक्त प्रांत, आसाम, सेण्ट्रल प्रांतों को, स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्राम सभाओं की समाप्ति से शिक्षा का ढाँचा चरमरा गया था, इसलिए सरकार ने आवश्यक नियम बनाये तथा प्रचलित नियमों में संशोधन किया।

अंग्रेजी को नीति के रूप में अपनाने पर गाँवों की प्रणाली पर आघात पहुँचा और उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना विचलित हो गयी। भारत के गाँवों पर केन्द्रीय प्रणाली लाद दी गयी औरप्राथमिक शिक्षा के खर्च के बहन करने के लिए नियम बनाये गये। निकायों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित पैसा प्राथमिक शिक्षा के लिए हो व्यय किया जाये। बम्बई सरकार ने आधी धनराशि स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए दी। चंगाल, पंजाब, संयुक्त प्रांत, आसाम, सेण्ट्ल प्रांतों को, स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्राम सभाओं की समाप्ति से शिक्षा का दाँचा चरमरा गया था, इसलिए सरकार ने आवश्यक नियम बनाये तथा प्रचलित नियमों में संशोधन किया । अंग्रेजी को नीति के रूप में अपनाने पर गाँवों की प्रणाली पर आघात पहुंचा और उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना विचलित हो गयी। भारत के गाँवों पर केन्द्रीय प्रणाली लाद दी गयो और गाँव, सरकारों को प्राणदान इकाइयाँ बन गये ग्रामों की प्रजातांत्रिकता नष्ट हो गयी थी और इसका देशी शिक्षण संस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 19वीं सदी के अन्त तक अनादि काल से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गयी। सरकारी उपेक्षा से कुछ विद्यालय समाप्त हो गये और कुछ सरकारी स्कूल प्रणाली में आत्मसात हो गये । गाँवों के स्कूलों के संरक्षक भी गाँव छोड़ शहरों में बसने लगे । अनेक मध्यम वर्गीय लोग रोजगार की तलाश में शहर में आ गये। ग्राम शिक्षा व्यवस्या डिन्नि भिन्न हो गयी।

वर्तमान प्रकार की प्राथमिक शिक्षा देश में अधिक ग्रहण होती जा रही थी। इस काल में स्थानीय निकायों ने प्राथमिक शिक्षा के व्यय में वृद्धि की किन्तु सरकारी नीति इसके विपरीत थी। 118। - 82 में प्राथमिक शिक्षा बजट ।6.77 लाख थी जो 1902 में 16.92 लास रहा। इससे सरकार को नीयत स्पष्ट होती है। इतना होने पर भी उदग्

(Vertical) रूप से प्राथमिक शिक्षा में प्रगति हो रही थी। शिक्षा, पादयक्रम में प्रकृति स्पष्ट दियो दं रही थी परन्तु प्रसार धीमा था।

4. मिशनरियों की संस्था

आयोग की रिपोर्ट ने ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के प्रयासों को धक्का पहुँचाया । किन्तु इसलिए मिशनरियों ने अपने नीति में परिवर्तन किया । उन्होंने उच्च शिक्षा से अपना ध्यान हटाया और जन शिक्षा के प्रसार में लग गये। आदिवासियों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में धर्म प्रसार का कार्य आरम्भ किया तो भारत में क्रिश्चियन जनसंख्या में वृद्धि होने लगी । भारतीय क्रिश्चियन के लिए उन्होंने स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना की। इस दौरान इंडियन क्रिश्चियन कॉलेज (इंदौर), में कॉलेज (सियालकोट), क्राईस्ट चर्च कॉलेज (कानपुर), गोर्डन कॉलेज (एग्लपिंडी) खोले गये ।

5. स्त्रियों की शिक्षा

आयोग की सिफारिशों के नारी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1,24,491 बालिकायें थीं। 1902 में यह संख्या 3,48,510 हो गयी। इनमें से 1,62,164 बालिकायें लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थी। हिन्दू बालिकाओं की संख्या 230,024 थी और मुसलमान बालिकाओं की 47,567 । छात्राओं के पाठ्यक्रम में संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी।

माध्यमिक शिक्षा भी लड़कियों में लोकप्रिय हो रही थी । छात्राओं तथा बालिका विद्यालयों को संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, अभारकर, महादेव गोबिन्द रानाडे, बैराज जी मालाबार आदि निस्वार्थ समाज सेवकों के प्रयास से बालिका विद्यालय खोले जा रहे थे ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नारी शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। 1882 में कुल 6 छात्रायें कॉलेजों में पढ़ रही थीं। 1902 में यह संख्या 264 हो गयो हिन्दू छात्राओं की संख्या 28 थी ।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति भी धीमी थी। 2808 लड़कियाँ विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ रही थी। इनमें अधिकांश लड़कियाँ ईसाई थी मेडिकल को चिकित्सा पर विशेष झुकाव था ।

6. मुसलमानों की शिक्षा

सर सैय्यद अहमद खां के प्रयास तथा सरकार के प्रोत्साहन से मुस्लिमों में शिक्षा के प्रति झुकाव होने लगा था। 1902 में सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं में मुस्लिम छात्रों की संख्या 9.73.000 थो । मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या कुल पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का 21.6 प्रतिशत था।

7. परिजन तथा अन्य वर्गों की शिक्षा

1882 से 1902 के हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा में विशेष प्रगति हुई। इसका कारण यह था कि सरकारी विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। इसके काहण (1) प्रवेश समानता. (2) सवर्ण हिन्दुओं के विरोध की समाप्ति (3) प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा महात्मा ज्योतिबा फुले अस्पृश्यता निवारण का आन्दोलन चल रहे थे, (4) जन आंदोलन के कारण पिकड़े बर्गो में शिया के अधिकार को माँग बल पड़ने लगी। (5) अन्तरिम सरकार हरिजन तथा अन्य नाग की शिक्षा की उदारता दिखायी। पढ़ने वाले छात्रों को दो रुपया मासिक को अतिरिक्त छात्रवृत्ति अस्पूर्यों को प्रवेश देन बाले गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त सहायता स्थानीय निकाय द्वारा शिक्षण संस्था खोलने पर बल सभी

पाठशालाओं को व्यवस्था से शिक्षा की प्रगति हुई।

8, आदिवासी तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा

आयोग की सिफारिशों के अनुसार आदिवासियों तथा पहाड़ों जातियों को शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों का निर्माण, नि:शुल्क शिक्षा, पत्तियों, शिक्षक प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता नि:शुल्क पाठ्य सामग्री की व्यवस्था की गयी। ईसाई मिशनरियों ने छोटानागपुर: संथाल [परगना, मदाम भसाम क दिबासियो तथा पहाी कों में शिक्षा प्रसार किया।

१. व्यावसायिक शिक्षा

आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए कानून चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, बनाम ज्ञान, कता. वाणिज्य प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा मस्था तोगयी पृथक सामाजिक, और कानून कॉलेजों के साथ साथ आर्ट्स कॉलेज भी कानून की शिक्षा दे सकते थे । आयोग की सिफारिशों के कारण इस दिशा में प्रगति हुई।

व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था-(1) सार्वजनिक प्रशासन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्यार करना, (2) प्राविधिक संस्थान में रोजगार उत्पन्न करना, (3) कानून, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र का विकास करना ।

वास्तविकता यह है कि 1882 के हंटर आयोग की सिफारिशों के कारण शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई, उससे सामाजिक चेतना का विकास हुआ।

7.4.2 हण्टर आयोग का मूल्यांकन (Evaluation of Hunter Commission) हण्टर कमीशन का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। कमीशन की जाँच के परिणामस्वरूप भारत में शैक्षिक जागृति हुई तथा एक निश्चित नीति का सूत्रपात हुआ। देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल विछ गया। अंग्रेजी स्कूलों तथा कॉलेजों तथा कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ।

आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित दोष भी थे।

1. आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए शिक्षा का अभाव था।

2, समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो स्पष्ट वर्गों में बाँट दिया।

3. पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल था।

4. आयोग ने सार्थजनिक शिक्षा की अवहेलना की।

आयोग की सिफारिशें के संबंध में ए० एन० बसु ने लिखा है कि आयोग ने लगभग उन्हीं सिद्धान्तों को दुहराया, जिनको वर्षों पूर्व युद्ध के आदेश पत्र में स्वीकार किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग ने उन सिद्धान्तों में से कुछ को केवल विस्तृत किया तथा कुछ पर यत्र तत्र थोड़ा सा बल दिया।
7.5 सारांश ( Summary)

सन् 1854 में कम्पनी शासन द्वारा शासन द्वारा शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसे कम्पनी के संचालक मंडल के अध्य सर चार्ल्स बु के नाम पर युद्ध का घोषणापत्र (W ood's Dispatch) कहा जाता है। इस घोषणा पत्र के तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण ता भविष्य में बौद्धिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा हुआ पासी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया था। इसलिए कभी कभी इस घोषणापत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा (Magna Carta of English education in India) अर्थात् माध्यम प्रान्त भाषा हो जेकी उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा हो (ग) शिक्षा व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर जनसाधारण के लिए हो (प) अध्यापकों के प्रशिक्षण को कक्षायें प्रारंभ की जायें (च) भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों को स्थापना की जायें। तब सन् 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास म विश्वविद्यालयों को स्थापना की गयी। इसी वर्ष ब्रिटिश संसद ने भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लो। तब भारत को शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया। सन् 1871 में शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

महादेश भी कहा जाता है। इस घोषणापत्र में स्वीकार किया गया था कि (क) भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का नैतिक तथा भौतिक विकास होना चाहिए (ख) छोटो कक्षाओं में शिक्षा का

किया गया। सन् 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन वह दूसरा प्रमुख प्रयास था जिसमें भारतीय शिक्षा नीति का पुनरीक्षण व स्पष्टीकरण विस्तार से किया गया था भारतीय शिक्षा आयोग के इस

अध्यक्ष सर विलियम हण्टर ने, जिनके नाम पर इस आयोग को हण्टर आयोग भी कहा जाता है आयोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षा का उत्तरदायित्व योग्य सार्वजनिक या वैयक्तिक संस्थानों को सौंप देना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि आधिकारिक स्थानीय सहयोग प्राप्त करने के लिए सहायक अनुदान उदारता से दिये जायें आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के चयन के लिए पाठ्य पुस्तक समिति बनाने तथा भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में सरकारी सहायता के सम्बन्ध में भी सिफारिश की थी।

7.6 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. 1854 के युद्ध के घोषणा पत्र की प्रमुख 2. 'बुद्ध का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महापिकार हैं।' विश्लेषण कीजिए। ("Wood's Despatch is called the Magna Charta of Indian education." Discuss.)

3. बुड के घोषणा पत्र के प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व का मूल्यांकन
सिफारिशों कीजिए।

(Examine the main recommendations of the Wood's Despatch of 1854.)

(What were the important provisions of Wood's Despatch? What is its Importance in the History of Indian education?)

4, हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का सविस्तार वर्णन करें।

(Elaborate the chief recommendations of Hunter Commission.)
1
882 के भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन सी थी और उन्होंने भारत

में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया? (What are the main recommendations of the Indian education commission of 1882 and how did they Influence education In India?)

1582 से 1902 तक की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राथमिक माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अद्भुत प्रसार था,